जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 37 संख्याः 358 प्रभात अजमेर, गुरूवार 6 अगस्त, 2026 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

केन्द्रीय संसदीय मंत्री रिजिजू राहुल गांधी से मिले और परिसीमन बिल व महिला आरक्षण पर सहयोग मांगा

प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकातें बढ़ाईं, क्योंकि मोदी को लगता है कि बार-बार मुलाकात करने से राहुल का रुख नरम पड़ेगा

- राहुल गांधी का आरोप है कि संसद का विशेष सत्र बुलाना और परिसीमन व महिला आरक्षण बिल पेश करना सरकार की मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति का अंग है।
- एक प्रमुख सवाल यह है कि जब संसद का नियमित सत्र ही नहीं चल पा रहा है तो क्या विपक्ष विशेष सत्र को चलने देगा, वैसे भी परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल संवैधानिक संशोधन हैं, इन्हें ध्वनिमत से या हंगामे के बीच पारित नहीं किया जा सकता है।
- राहुल गांधी ने 10, जनपथ, के बाहर कुछ छात्रों की मीडिया से मुलाकात करवाई और 20 जुलाई को क्या हुआ इसकी जानकारी दी।
- राहुल ने कहा, गृह मंत्री सदन में आकर देश को क्यों नहीं बताते कि उस दिन क्या हुआ था, छात्रों पर पैलैट गन चलाने, आँसू गैस छोड़ने व लाठी चार्ज करने का आदेश क्या उन्होंने दिया था।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अगस्त। संसद में गतिरोध लगातार जारी है। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित हो रही है। इसी बीच सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा और उन्हें पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अब भी दोनों सदनों से लगातार अनुपस्थित हैं, विपक्ष यह जानना चाहता है कि छात्रों पर हमला करने और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था।

संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा, लेकिन सरकार 17, 18 और 19 अगस्त को विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा कर उन्हें पारित कराना चाहती है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में राहुल गांधी के कार्यालय में जाकर उनसे मुलाकात की और दोनों विधेयकों पर समर्थन मांगा।

राहुल गांधी ने साफ कहा कि अमित शाह को सदन में आकर छात्रों पर पुलिस की बर्बरता पर बयान देना होगा। प्रधानमंत्री को भी "चढ़ावा दा चोरी" के मुद्दे पर बोलना चाहिए। परिसीमन विधेयक में बदलाव किए जाने चाहिए और इस बारे में वे विपक्ष के अपने सहयोगियों से भी चर्चा करेंगे।

कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू को अपने संसद कार्यालय आने का निमंत्रण दिया था, जहां दोनों की मीटिंग हुई थी।

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री को प्रतिवेदन सौंपा

जयपुर, 5 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी एवं सदस्यों ने भेंट की तथा उन्हें पंचायती एवं नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सौंपा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत

- इससे पंचायत तथा नगरीय निकायों के चुनावों में आरक्षण का काम हो सकेगा।

करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। स्थानीय चुनावों को समय पर कराने का जो वादा किया था, उसकी ओर हम तेजी से बढ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वन स्टेट-वन इलेक्शन व्यवस्था से विकास और जनकल्याण के कार्यों को निरंतर गति मिलेगी। इससे पैसे, समय एवं संसाधनों की बचत होगी।

इस दौरान, पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, ओबीसी आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन एवं सदस्य प्रो. राजीव सक्सेना, गोपाल कृष्ण, मोहन मोरवाल और पवन मावंडिया सहित, अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

भारत की म्यांमार से जमीन की अदला-बदली की योजना खटाई में पड़ी

मणिपुर के सिविल सोसायटी संगठनों ने इसका भारी विरोध किया और कहा कि मणिपुर की भूमि की अदला-बदली किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी

- केन्द्र सरकार म्यांमार से जमीन एक्सचेंज इसलिए चाहती है, ताकि सीमा पर तारबंदी की जा सके, और ड्रग्स तस्करी और आतंकियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया जा सके। ज्ञातव्य है कि भारत व म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लम्बी सीमा है, जिसमें से 171 किलोमीटर क्षेत्र अभी भी विवादित है।
- मणिपुर में मैतेई समुदाय के संगठन, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी,ने तर्क दिया कि 1949 में भारत में विलय के समय मणिपुर को बड़ा भू-भाग गंवाना पड़ा था और अब मणिपुर के क्षेत्र में किसी भी कमी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- इस सीमा विवाद की जड़ ब्रिटिश राज से संबंधित है। प्रथम एंग्लो-बर्मा युद्ध के बाद यांडाबो संधि ने सीमा निर्धारण की दिशा तय की। सन् 1834 में कबाव घाटी बर्मा (म्यांमार) को सौंप दी गई, इसके बदले मणिपुर को मुआवजा दिया गया।
- वर्ष 1937 में बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हो गया। वर्ष 1967 में भारत बर्मा के बीच औपचारिक सीमा निर्धारण हुआ, पर, कबाव घाटी में सीमांकन नहीं हो पाया। इसलिए सीमा विवाद अभी भी जारी है।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अगस्त। पूर्वोत्तर में एक नया विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। मणिपुर के कई सिविल सोसायटी संगठनों ने केन्द्र सरकार की उस कथित योजना का कड़ा विरोध किया है, जिसके तहत म्यांमार के साथ सीमावर्ती जमीन की अदला-बदली की जा सकती है।

रिपोर्टों और अगस्त 2026 की शुरुआत में विदेश मंत्रालय के बयानों के अनुसार, भारत और म्यांमार मणिपुर के चंदेल जिले में दोनों देशों की साझा सीमा के अनिर्धारित हिस्से के लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने के लिए सीमित स्तर पर जमीन की अदला-बदली पर चर्चा कर रहे हैं।

मई 2026 के एक आधिकारिक दस्तावेज में उल्लिखित एक प्रस्ताव, जिसका सबसे पहले उल्लेख द डिप्लोमैट ने किया था, के अनुसार, सीमा स्तंभ (बॉर्डर पिलर्स) संख्या 65 से 68 के बीच लगभग 1.4 वर्ग मील (करीब 3.6 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर राहुल ने सरकार का निवेदन ठुकराया

केन्द्र सरकार मौजूदा सत्र में इन बिलों को दोबारा लाना चाहती है और इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने उनके चैम्बर में गए

- राहुल गांधी ने साफ कहा कि सदन में तब तक काम नहीं होगा, जब तक राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा नहीं हो जाती और 20 जुलाई को हुए छात्र प्रोटैस्ट के दौरान छात्रों पर पुलिस एक्शन के मामले में अमित शाह संसद में बयान नहीं दे देते।
- सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने हाल ही में दलबदल के जरिए अपना संख्या बल बढ़ा लिया है, इसलिए सत्ता पक्ष परिसीमन बिल और महिला आरक्षण विधेयक को पुनः पेश करने के लिए बेहद उत्साहित है, पर, संयुक्त विपक्ष ने सरकार की इस रणनीति में रोड़ा अटका दिया है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अगस्त। संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध तीसरे सप्ताह में पहुंच गया है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संपर्क किया, ताकि इस गतिरोध का कोई रास्ता निकाला जा सके।

सूत्रों के अनुसार, लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद स्थगित कर दी गई, जिसके तुरंत बाद रिजिजू ने राहुल गांधी से उनके कक्ष में मुलाकात की।

सूत्रों के अनुसार, रिजिजू ने कांग्रेस से परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर सहयोग मांगा। सरकार इन दोनों विधेयकों को मौजूदा सत्र में फिर से पेश कर पारित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री ने एनडीए के नये राज्यसभा सांसदों से मुलाकात की

नई दिल्ली, 05 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों के साथ नाश्ते पर

- उन्हें संसद की कार्यवाही में नियमित रुप से उपस्थिति रहने की सलाह दी।

बैठक की। हाल ही में अन्य दलों से एनडीए और भाजपा में शामिल हुए सांसद भी बैठक में मौजूद रहे।

इनमें भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, स्वाति मालिवाल, विनोद तावड़े, सुजीत कुमार, अलका गर्जुर, अशोक मित्तल, तरुण चुग सहित कई सांसद शामिल रहे।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सांसदों को संसद की कार्यवाही में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंजाब भाजपा में नई नियुक्तियों ने आतंरिक असंतोष को उजागर किया

नई नियुक्तियों की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने शुरु कर दिए

- पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं को शिकायत है कि अन्य दलों से आए लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और जिन कार्यकर्ताओं ने राज्य में पार्टी को खड़ा किया उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है।
- अन्य दलों से आए नेताओं को भी शिकायत है कि उन्हें उनके राजनैतिक कद के अनुरुप पद नहीं दिया गया है। हालांकि, पार्टी ने 12 उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिनमें से 6 अन्य दलों से आए नेता हैं।
- इसके अलावा नई नियुक्तियों में भारी विसंगतियाँ हैं, जैसे 5 महासचिव नियुक्त किए गए हैं, इनमें से तीन लुधियाना से जुड़े हैं और अमृतसर, गुरदासपुर व होशियारपुर, जहाँ पार्टी का प्रभाव है, की अनदेखी की गई है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अगस्त। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारी का संदेश देना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय उसने अपने ही संगठन में गहराती अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया।

3 अगस्त को पार्टी ने पंजाब इकाई की नई टीम की घोषणा की। इसमें राज्य संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ छह जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। संगठनात्मक फेरबदल आमतौर पर कुछ असंतोष तो पैदा करते ही हैं, लेकिन इस बार मामला कहीं अधिक गंभीर हो गया।

घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से नियुक्तियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जबकि कई अन्य नेताओं ने निजी तौर पर अपनी नाराज़गी जताई। उनकी आपत्ति केवल नई टीम की संरचना को लेकर नहीं थी, बल्कि इस बात को लेकर भी थी कि पूरी प्रक्रिया किस तरह संचालित की गई।

आलोचना का केन्द्र भाजपा के संगठन महामंत्री मंत्री श्रीनिवासलु रहे, जो पंजाब में संगठन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। राज्य इकाई के भीतर उन्हें पार्टी के वास्तविक संगठनात्मक संचालन का प्रमुख माना जाने लगा है। यही धारणा अब बढ़ते असंतोष और विद्रोह का कारण बन रही है।

कई महीनों से पंजाब भाजपा के पुराने नेता शिकायत कर रहे हैं कि अब पार्टी में निष्ठा का महत्व नहीं रह गया है। उनका कहना है कि जिन्होंने उस दौर में पार्टी को खड़ा किया, जब उसका प्रभाव मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, उन्हें अब दरकिनार किया जा रहा है। उनका आरोप है कि योग्यता और वर्षों की मेहनत की जगह अब राजनीतिक सुविधा ने ले ली है। उनका मानना है कि हर नई नियुक्ति में उन नेताओं को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कैबिनेट सचिव व गृह सचिव का सेवाकाल एक वर्ष बढ़ा

नई दिल्ली, 05 अगस्त। केन्द्र सरकार ने कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन और गृह सचिव गोविंद मोहन की सेवा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है। यह जानकारी बुधवार को

- कैबिनेट सचिव सोमनाथन का रिटायरमेंट 30 अगस्त को तथा गृह सचिव गोविन्दर मोहन का 22 अगस्त को होना था।

जारी अलग-अलग आधिकारिक नोटिफिकेशनों में दी गई। जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सोमनाथन का रिटायरमेंट 30 अगस्त को निर्धारित था, वहीं गोविंद मोहन का रिटायरमेंट 22 अगस्त को था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिज़र्व बैंक ने नई क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया

रिज़र्व बैंक ने महंगाई पर नियंत्रण के बजाय भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के पक्ष में फैसला किया

- अभी महंगाई 5 प्रतिशत है, जबकि आरबीआई का लक्ष्य 4 प्रतिशत का था, आरबीआई व विशेषज्ञों के अनुसार, महंगाई 5 प्रतिशत होने में जयादा जोखिम नहीं है।
- प्राइवेट खपत में अपनी मर्ज़ी से किए जाने वाले खर्च की वजह से अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी रही और सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किए जाने वाले खर्च से भी निवेश गतिविधियों में स्थिरता है।
- वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में वाहनों की खुदरा बिक्री 14.5 प्रतिशत बढ़ी। दुपहिया वाहनों व ट्रैक्टर की खुदरा बिक्री भी क्रमशः 15.1 प्रतिशत और 21.4 प्रतिशत रही।
- स्टील की खपत 8.3 प्रतिशत बढ़ी और सीमेंट उत्पादन में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- निर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा, सर्विस सैक्टर ने भी अपनी गति कायम रखी, मजबूत घरेलू मांग के कारण।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अगस्त। आरबीआई गवर्नर ने तेजी से बढ़ती महंगाई को रोकने के बजाय, धीरे-धीरे बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने का विकल्प चुना।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज अपनी नई ऋण नीति की घोषणा की और नीतिगत ब्याज दरों (पॉलिसी इंटरैस्ट रेट्स) में कोई बदलाव नहीं किया। नीतिगत ब्याज दरें कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए सैन्ट्रल बैंक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बेहद महत्वपूर्ण साधन होती हैं।

पहली नज़र में यह फैसला कुछ अजीब लग सकता है, क्योंकि मौजूदा महंगाई दर आरबीआई के तय लक्ष्य से काफी ऊपर है। रिज़र्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि आने वाले महीनों से लेकर अगले वित्त वर्ष की शुरुआत तक महंगाई लगभग 5 प्रतिशत के आसपास रहेगी। इसके मुकाबले, आरबीआई का महंगाई लक्ष्य 4 प्रतिशत है।

महंगाई को टारगेट लैवल तक लाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने के बजाय, आरबीआई ने उन्हें यथावत रखने का फैसला इसलिए किया है, क्योंकि उसके विश्लेषण के अनुसार, यह महंगाई सीमित क्षेत्रों तक ही है और पूरे बाजार में व्यापक स्तर पर कीमतें बढ़ने का फिलहाल ज्यादा खतरा नहीं है।

महंगाई के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए आरबीआई ने कहा, "वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कंज्युमर प्राइस इण्डैक्स (सीपीआई) आधारित महंगाई 5.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। दूसरी तिमाही में यह 4.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.9 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2027-28 की पहली तिमाही में महंगाई 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें जोखिम बराबर रूप से संतुलित हैं।"

लेकिन आरबीआई ने बताया कि कोर महंगाई (जिसमें ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतें शामिल नहीं हैं) अभी भी संतोषजनक स्तर पर है। यानी, फिलहाल महंगाई का मौजूदा दबाव मुख्य रूप से केवल दो क्षेत्रों, ईंधन और खाद्य पदार्थों, से आ रहा है। इनमें भी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण पैदा हुई अस्थिरता है।

आरबीआई का मानना है कि युद्ध

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का विधेयक राज्यसभा में पारित

नई दिल्ली, 05 अगस्त। संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। इसके साथ ही देश के सर्वोच्च

- अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जायेगी।

न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह विधेयक लोकसभा से 3 अगस्त को पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केन्द्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)